

जयपुर जिले में महिला सशक्तिकरण एवं क्षेत्रीय विकास के बीच संबंध: एक भौगोलिक अध्ययन

रसप्रिया बैसला, शोधार्थी, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर Email: renubhesla@gmail.com

डॉ. सुमन (सहायक प्रोफेसर), ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर

सारांश

महिला सशक्तिकरण और क्षेत्रीय विकास के बीच संबंध समकालीन सामाजिक विज्ञान, विकास अध्ययन तथा मानव भूगोल का एक महत्वपूर्ण विषय है। किसी क्षेत्र का विकास केवल आय, उत्पादन, नगरीकरण अथवा भौतिक अवसंरचना की वृद्धि से निर्धारित नहीं होता, बल्कि उस क्षेत्र में महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक भागीदारी, संसाधनों तक पहुँच, निर्णय-निर्माण में सहभागिता, सामाजिक गतिशीलता, संस्थागत अवसरों तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व की स्थिति भी विकास की दिशा और गुणवत्ता को प्रभावित करती है। प्रस्तुत शोध-पत्र में जयपुर जिले को अध्ययन क्षेत्र के रूप में लेकर महिला सशक्तिकरण एवं क्षेत्रीय विकास के मध्य संबंध का सामाजिक, आर्थिक और स्थानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

जयपुर राजस्थान का प्रमुख प्रशासनिक, शैक्षिक, पर्यटन, व्यापारिक एवं सेवा क्षेत्रीय केंद्र है। 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 66,26,178 थी, जिसमें 34,68,507 पुरुष तथा 31,57,671 महिलाएँ थीं। जिले की कुल साक्षरता 75.51 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 64.02 प्रतिशत दर्ज की गई थी। इसी समय जिले में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का आकार लगभग तुलनीय था, जिससे जयपुर ग्रामीण-नगरीय संक्रमण का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बनता है।

अध्ययन का केंद्रीय तर्क यह है कि महिला सशक्तिकरण और क्षेत्रीय विकास का संबंध एक-दिशीय नहीं है। महिला शिक्षा, रोजगार, उद्यमिता, स्वयं सहायता समूह, वित्तीय समावेशन और स्थानीय शासन में भागीदारी क्षेत्रीय विकास को गति देती है; वहीं सड़क, बाजार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, डिजिटल संपर्क और रोजगार के अवसरों का विस्तार स्वयं महिलाओं के सशक्तिकरण को आगे बढ़ाता है। इस प्रकार दोनों के बीच परस्पर सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया विकसित होती है।

शोध-पत्र में द्वितीयक आँकड़ों, सरकारी प्रतिवेदनों, जनगणना सामग्री तथा विकास एवं महिला सशक्तिकरण संबंधी सैद्धांतिक साहित्य का उपयोग किया गया है। विश्लेषण में महिला शिक्षा, आर्थिक भागीदारी, स्वयं सहायता समूह, वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य, राजनीतिक सहभागिता, अवसंरचना, ग्रामीण-नगरीय विभाजन तथा स्थानिक असमानता को प्रमुख विश्लेषणात्मक आयाम माना गया है।

अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि महिला सशक्तिकरण को क्षेत्रीय विकास का केवल परिणाम मानना पर्याप्त नहीं है; यह स्वयं विकास की उत्पादक शक्ति है। सशक्त महिला परिवार की मानव पूँजी को मजबूत करती है, स्थानीय अर्थव्यवस्था में भाग लेती है, आय सृजित करती है, सामुदायिक संस्थाओं को सक्रिय करती है और स्थानीय विकास की प्राथमिकताओं को प्रभावित करती है। इसलिए जयपुर के संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए महिला केंद्रित स्थानिक नियोजन की आवश्यकता है।

प्रमुख शब्द: महिला सशक्तिकरण, क्षेत्रीय विकास, महिला शिक्षा, आर्थिक भागीदारी, स्वयं सहायता समूह, ग्रामीण विकास, नगरीकरण, जयपुर जिला, मानव भूगोल, क्षेत्रीय असमानता।

1. प्रस्तावना

भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका ऐतिहासिक रूप से परिवार, कृषि, हस्तशिल्प, स्थानीय अर्थव्यवस्था, सामाजिक पुनरुत्पादन और सामुदायिक जीवन के विविध स्तरों पर रही है। आधुनिक विकास प्रक्रिया ने इस भूमिका को नए आयाम प्रदान किए हैं। शिक्षा के विस्तार, नगरीकरण, बाजार अर्थव्यवस्था, स्वयं सहायता समूहों, वित्तीय संस्थाओं, डिजिटल तकनीक और स्थानीय लोकतांत्रिक संस्थाओं के विस्तार ने महिलाओं के लिए पहले की अपेक्षा अधिक व्यापक अवसर उपलब्ध कराए हैं। इसके बावजूद अवसरों का स्थानिक वितरण समान नहीं है। यही असमानता महिला सशक्तिकरण के भौगोलिक अध्ययन को आवश्यक बनाती है।

परंपरागत क्षेत्रीय विकास अध्ययनों में उत्पादन, आय, औद्योगिकीकरण, नगरीकरण और अवसंरचना को विकास के प्रमुख संकेतक माना जाता था। मानव विकास की अवधारणा के विस्तार के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, सामाजिक अवसर और क्षमता विकास को भी विकास के केंद्रीय घटक के रूप में स्वीकार किया गया। अमर्त्य सेन का क्षमता दृष्टिकोण इस बहस को आगे बढ़ाते हुए यह स्पष्ट करता है कि विकास का वास्तविक अर्थ लोगों की वास्तविक स्वतंत्रताओं और विकल्पों का विस्तार है। महिला सशक्तिकरण इसी क्षमता विस्तार का प्रमुख पक्ष है।

जयपुर जिले का अध्ययन विशेष महत्व रखता है क्योंकि राजधानी क्षेत्र, तीव्र नगरीकरण, पर्यटन, सेवा क्षेत्र, शिक्षा संस्थानों, व्यापार, हस्तशिल्प तथा व्यापक ग्रामीण परिक्षेत्र की सह-अवस्थिति इसे सामाजिक-आर्थिक संक्रमण का विशिष्ट क्षेत्र बनाती है। 2011 की जिला जनगणना पुस्तिका में जयपुर की कुल जनसंख्या 66,26,178 दर्ज की गई, जिसमें 31,54,331 ग्रामीण तथा 34,71,847 नगरीय जनसंख्या थी।

2. अध्ययन की समस्या

प्रस्तुत शोध की मूल समस्या यह है कि जयपुर जिले में महिला सशक्तिकरण के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और संस्थागत आयाम क्षेत्रीय विकास की दिशा और तीव्रता को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। साथ ही यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि जिन स्थानों पर शिक्षा, बाजार, परिवहन, स्वास्थ्य, बैंकिंग और रोजगार की सुविधाएँ अधिक हैं, वहाँ महिलाओं के सशक्तिकरण की स्थिति किस प्रकार बदलती है। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के बीच यह संबंध किस सीमा तक भिन्न है, यह भी शोध का केंद्रीय प्रश्न है। शोध समस्या को संक्षेप में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है— “जयपुर जिले में महिला सशक्तिकरण तथा क्षेत्रीय विकास के बीच किस प्रकार का पारस्परिक, स्थानिक और सांख्यिकीय संबंध विद्यमान है?”

3. अध्ययन के उद्देश्य

जयपुर जिले में महिला सशक्तिकरण की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करना।

महिला शिक्षा और क्षेत्रीय विकास के बीच संबंध का भौगोलिक विश्लेषण करना।

महिलाओं की आर्थिक भागीदारी, रोजगार और उद्यमिता का अध्ययन करना।

ग्रामीण एवं नगरीय महिलाओं के सशक्तिकरण में स्थानिक अंतर स्पष्ट करना।

स्वयं सहायता समूहों और वित्तीय समावेशन की भूमिका का मूल्यांकन करना।

स्थानीय शासन एवं निर्णय-निर्माण में महिलाओं की सहभागिता का अध्ययन करना।

महिला सशक्तिकरण और क्षेत्रीय विकास के पारस्परिक संबंध का विश्लेषण करना।

जयपुर जिले में महिला सशक्तिकरण के समक्ष भौगोलिक एवं सामाजिक बाधाओं की पहचान करना।

क्षेत्रीय असमानता को कम करने के लिए स्थान-विशिष्ट नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना।

4. शोध परिकल्पनाएँ

परिकल्पना 1: जयपुर जिले में महिला सशक्तिकरण के उच्च स्तर और क्षेत्रीय विकास के उच्च स्तर के बीच सार्थक सकारात्मक संबंध पाया जाता है।

परिकल्पना 2: नगरीय क्षेत्रों की महिलाओं की शिक्षा, रोजगार, वित्तीय पहुँच एवं निर्णय-निर्माण की स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की अपेक्षा अधिक सशक्त है।

परिकल्पना 3: महिला शिक्षा और आर्थिक भागीदारी में वृद्धि क्षेत्रीय सामाजिक-आर्थिक विकास के प्रमुख निर्धारकों में से एक है।

5. अध्ययन की भौगोलिक पृष्ठभूमि: जयपुर जिला

जयपुर राजस्थान के पूर्व-मध्य भाग का प्रमुख प्रशासनिक एवं आर्थिक क्षेत्र है। राजधानी के रूप में इसकी भूमिका ने शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, वित्त, पर्यटन, सेवा गतिविधियों तथा व्यापारिक संरचनाओं को मजबूत किया है। दूसरी ओर जिले के ग्रामीण हिस्सों में कृषि, पशुपालन, ग्रामीण श्रम, हस्तशिल्प और सूक्ष्म उद्यम आजीविका के महत्वपूर्ण आधार हैं। इस ग्रामीण-नगरीय द्वैत के कारण महिला सशक्तिकरण के अवसरों और परिणामों में आंतरिक भौगोलिक विविधता की संभावना रहती है।

केंद्रीय भूजल बोर्ड की जयपुर संबंधी जिला रिपोर्ट में जयपुर की प्रशासनिक राजधानी, पर्यटन गतिविधियों तथा सांगानेर-बगरू से जुड़े मुद्रण उद्योग जैसे आर्थिक-सांस्कृतिक पक्षों का उल्लेख मिलता है। यह तथ्य बताता है कि महिलाओं के लिए आजीविका के अवसरों का आधार कृषि से आगे बढ़कर सेवा, पर्यटन, हस्तशिल्प एवं लघु उद्योगों तक विस्तृत हो चुका है।

तालिका 1 : जयपुर जिले की चयनित जनसांख्यिकीय विशेषताएँ

मान	संकेतक	वर्ष
66,26,178	कुल जनसंख्या	2011
34,68,507	पुरुष जनसंख्या	2011
31,57,671	महिला जनसंख्या	2011
31,54,331	ग्रामीण जनसंख्या	2011
34,71,847	नगरीय जनसंख्या	2011
75.51%	कुल साक्षरता	2011
64.02%	महिला साक्षरता	2011
86.05%	पुरुष साक्षरता	2011
910	लिंगानुपात	2011
861	0-6 आयु वर्ग लिंगानुपात	2011

स्रोत : भारत की जनगणना, 2011; जिला जनगणना पुस्तिका, जयपुर।

6. महिला सशक्तिकरण: संकल्पना और आयाम

महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं को केवल औपचारिक अधिकार देना नहीं, बल्कि ऐसी सामाजिक, आर्थिक और संस्थागत परिस्थितियों का निर्माण करना है जिनमें वे उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर सकें, स्वतंत्र निर्णय ले सकें, अपनी आय और श्रम पर प्रभावी नियंत्रण रख सकें तथा सार्वजनिक जीवन में सार्थक भागीदारी कर सकें। नुसबाम और सेन की क्षमता आधारित दृष्टियों के संदर्भ में सशक्तिकरण को विकल्पों, क्षमताओं और स्वतंत्रताओं के विस्तार से जोड़ा जा सकता है।

भौगोलिक अध्ययन में महिला सशक्तिकरण के पाँच प्रमुख आयाम उपयोगी हैं— शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और संस्थागत। इन आयामों के साथ डिजिटल पहुँच को आधुनिक संदर्भ में एक स्वतंत्र लेकिन अंतर्संबद्ध आयाम के रूप में जोड़ा जा सकता है।

शैक्षिक सशक्तिकरण : साक्षरता, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण तथा डिजिटल शिक्षा।

आर्थिक सशक्तिकरण: रोजगार, स्व-रोजगार, उद्यमिता, आय, बैंकिंग तथा संपत्ति पर नियंत्रण।

सामाजिक सशक्तिकरण: स्वास्थ्य, गतिशीलता, सामाजिक प्रतिष्ठा और परिवार में निर्णय क्षमता।

राजनीतिक सशक्तिकरण: पंचायत, नगर निकाय तथा स्थानीय निर्णय-निर्माण में सहभागिता।

संस्थागत सशक्तिकरण: स्वयं सहायता समूह, सरकारी योजनाएँ, वित्तीय संस्थाएँ और प्रशिक्षण नेटवर्क।

7. क्षेत्रीय विकास की भौगोलिक अवधारणा

क्षेत्रीय विकास का अर्थ किसी विशिष्ट भू-भाग की भौतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं मानवीय क्षमताओं में संतुलित सुधार से है। विकास की भौगोलिक प्रक्रिया क्षेत्र के संसाधनों, स्थानिक संरचना, परिवहन नेटवर्क, बाजार, संस्थानों और मानव पूँजी से प्रभावित होती है। इसलिए महिला सशक्तिकरण को क्षेत्रीय विकास से अलग नहीं किया जा सकता। महिला श्रम और ज्ञान का अधिक उपयोग क्षेत्र की उत्पादन क्षमता बढ़ा सकता है, जबकि विकास के बेहतर अवसर महिलाओं की क्षमताओं और स्वतंत्रताओं को विस्तृत कर सकते हैं।

8. महिला शिक्षा और क्षेत्रीय विकास

महिला शिक्षा महिला सशक्तिकरण का सबसे आधारभूत आयाम है। शिक्षित महिला केवल व्यक्तिगत रूप से सक्षम नहीं होती, बल्कि परिवार के स्वास्थ्य, पोषण, बच्चों की शिक्षा, विवाह संबंधी निर्णय, संसाधन उपयोग और आर्थिक व्यवहार पर भी

सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इस कारण महिला शिक्षा को क्षेत्रीय मानव पूँजी का प्रमुख घटक माना जाना चाहिए। जयपुर जिले की महिला साक्षरता 64.02 प्रतिशत तथा पुरुष साक्षरता 86.05 प्रतिशत थी। यह दर्शाता है कि जयपुर की स्थिति राज्य औसत की तुलना में बेहतर होने के बावजूद लैंगिक अंतर बना हुआ था। यह अंतर ग्रामीण-नगरीय दूरी, सामाजिक मानदंड, विद्यालय तक पहुँच, परिवहन तथा उच्च शिक्षा की लागत जैसे कारकों से जुड़ सकता है।

तालिका 2 : राजस्थान और जयपुर में साक्षरता की तुलना

राजस्थान	जयपुर	संकेतक
66.11%	75.51%	कुल साक्षरता
79.19%	86.05%	पुरुष साक्षरता
52.12%	64.02%	महिला साक्षरता
27.07 अंक	22.03 अंक	पुरुष-महिला साक्षरता अंतर

स्रोत : राजस्थान सरकार के शिक्षा संबंधी जिला-वार आँकड़े एवं जनगणना 2011।

9. ग्रामीण-नगरीय विभाजन और महिला सशक्तिकरण

जयपुर जिले की ग्रामीण और नगरीय आबादी का लगभग तुलनीय आकार इस अध्ययन को विशिष्ट बनाता है। नगरीय क्षेत्रों में उच्च शिक्षा, अस्पताल, बैंक, परिवहन, निजी रोजगार, सेवा क्षेत्र तथा डिजिटल कनेक्टिविटी अपेक्षाकृत सघन है। दूसरी ओर ग्रामीण महिलाओं का रोजगार कृषि, पशुपालन, घरेलू उत्पादन, हस्तशिल्प और सामुदायिक समूहों से अधिक जुड़ा हो सकता है।

यह निष्कर्ष वैज्ञानिक रूप से उचित नहीं होगा कि सभी ग्रामीण महिलाएँ कम और सभी नगरीय महिलाएँ अधिक सशक्त हैं। वास्तविक अंतर संसाधनों और अवसरों की पहुँच, निर्णय शक्ति, आय पर नियंत्रण और सामाजिक गतिशीलता से निर्धारित होता है। अतः स्थान को सशक्तिकरण का प्रत्यक्ष कारण मानने के बजाय स्थानिक अवसर संरचना को विश्लेषण का केंद्र बनाया जाना चाहिए।

10. महिला आर्थिक भागीदारी और क्षेत्रीय विकास

किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में महिला श्रम की वास्तविक भूमिका उसके औपचारिक रोजगार आँकड़ों से कहीं अधिक व्यापक होती है। कृषि, पशुपालन, घरेलू उद्योग, देखभाल कार्य, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यापार और पारिवारिक व्यवसायों में महिलाओं का योगदान अक्सर आँकड़ों में पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता। इसीलिए महिला आर्थिक सशक्तिकरण का अध्ययन करते समय भुगतानयुक्त और अवैतनिक दोनों प्रकार के श्रम को ध्यान में रखना चाहिए।

जयपुर में सेवा क्षेत्र, पर्यटन, हस्तशिल्प, वस्त्र, मुद्रण, शिक्षा, स्वास्थ्य, लघु व्यापार तथा सूक्ष्म उद्यम महिला आर्थिक भागीदारी के संभावित क्षेत्र हैं। आर्थिक गतिविधि में महिलाओं की भागीदारी केवल आय नहीं बढ़ाती, बल्कि परिवार और स्थानीय अर्थव्यवस्था में क्रय शक्ति तथा संसाधन परिसंचरण को भी बढ़ाती है।

11. स्वयं सहायता समूह और ग्रामीण महिला सशक्तिकरण

स्वयं सहायता समूह महिला सशक्तिकरण और क्षेत्रीय विकास के बीच एक महत्वपूर्ण संस्थागत पुल हैं। बचत, सामूहिक ऋण, प्रशिक्षण, बाजार, वित्तीय साक्षरता और सामुदायिक नेतृत्व के माध्यम से समूह महिलाओं को निजी जीवन से सार्वजनिक आर्थिक जीवन की ओर ले जा सकते हैं।

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के जिला-वार उपलब्ध आँकड़ों में जयपुर के लिए राजीविका द्वारा गठित 16,223 स्वयं सहायता समूह तथा अन्य विभागों/गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रवर्तित 780 समूह, कुल 17,003 समूह दर्ज हैं। यह संस्थागत विस्तार ग्रामीण महिला सामूहिकीकरण की महत्ता को दर्शाता है।

तालिका 3 : जयपुर में स्वयं सहायता समूहों का संस्थागत विस्तार

समूहों की संख्या	श्रेणी
16,223	राजीविका द्वारा गठित समूह

780	अन्य विभाग एवं गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रवर्तित समूह
17,003	कुल समूह

स्रोत : राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद का जिला-वार प्रतिवेदन।

12. महिला उद्यमिता और स्थानीय अर्थव्यवस्था

महिला उद्यमिता स्थानीय क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता बढ़ाने का साधन है। सूक्ष्म और लघु व्यवसाय महिलाओं की आय बढ़ाने के साथ-साथ स्थानीय रोजगार तथा बाजार की मांग को भी बढ़ा सकते हैं। राजस्थान के आर्थिक प्रतिवेदनों में महिला उद्यमों, स्वयं सहायता समूह उत्पादों तथा महिला संचालित आर्थिक गतिविधियों के विस्तार की दिशा स्पष्ट होती है।

जयपुर की पारंपरिक शिल्प-आधारित अर्थव्यवस्था, वस्त्र, मुद्रण, पर्यटन तथा सेवाक्षेत्र में महिला उद्यमिता के लिए अनुकूल अवसर मौजूद हैं। फिर भी पूँजी, विपणन, डिजिटल कौशल, संपत्ति स्वामित्व, परिवहन और पारिवारिक दायित्व जैसे अवरोध महिला उद्यमिता को सीमित कर सकते हैं।

13. वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण

महिला सशक्तिकरण तब अधिक गहरा होता है जब महिला बैंकिंग, बचत, ऋण, बीमा और डिजिटल वित्तीय सेवाओं तक वास्तविक पहुँच बनाती है। केवल बैंक खाता खुलना पर्याप्त नहीं है; खाते का संचालन, वित्तीय निर्णय और ऋण के उपयोग पर महिला का नियंत्रण अधिक महत्वपूर्ण है।

राजस्थान की ग्रामीण आजीविका व्यवस्था में बैंक सखी और समुदाय आधारित वित्तीय कार्यकर्ताओं की भूमिका महिलाओं को औपचारिक वित्तीय तंत्र से जोड़ने में सहायक रही है। ऐसी व्यवस्थाएँ वित्तीय समावेशन को स्थानीय सामाजिक पूँजी से जोड़ती हैं।

14. राजनीतिक सशक्तिकरण और स्थानीय शासन

स्थानीय शासन महिला सशक्तिकरण का प्रत्यक्ष राजनीतिक आयाम है। पंचायतों और नगर निकायों में महिला प्रतिनिधित्व ने महिलाओं को सार्वजनिक निर्णय-निर्माण के औपचारिक मंच दिए हैं। किंतु केवल निर्वाचित होना और वास्तविक निर्णय क्षमता दो अलग स्थितियाँ हैं। इसलिए महिला प्रतिनिधित्व की गुणवत्ता का परीक्षण ग्रामसभा सहभागिता, बजट प्राथमिकता निर्धारण, स्थानीय योजनाओं में सक्रियता तथा स्वतंत्र निर्णय-निर्माण से किया जाना चाहिए।

जयपुर के ग्रामीण क्षेत्र में महिला प्रतिनिधियों की भूमिका शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, पोषण, सामाजिक सुरक्षा और स्थानीय अवसंरचना जैसे विषयों की प्राथमिकताओं को प्रभावित कर सकती है। इस प्रकार राजनीतिक सशक्तिकरण सामाजिक विकास को प्रत्यक्ष दिशा प्रदान करता है।

15. महिला स्वास्थ्य और क्षेत्रीय विकास

महिला स्वास्थ्य को मानव विकास के साथ-साथ क्षेत्रीय विकास का आर्थिक घटक भी माना जाना चाहिए। स्वस्थ महिला श्रम बाजार, परिवार और सामुदायिक जीवन में अधिक सक्रिय भागीदारी कर सकती है। मातृ स्वास्थ्य, पोषण, प्रजनन स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की दूरी महिला सशक्तिकरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं।

जयपुर के नगरीय क्षेत्रों में उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता अपेक्षाकृत अधिक है, जबकि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन, दूरी और सेवा की नियमितता बाधा बन सकती है। इसलिए स्वास्थ्य सुविधाओं का स्थानिक वितरण महिला सशक्तिकरण की भौगोलिक विषमता को समझने का महत्वपूर्ण आधार है।

16. अवसंरचना, गतिशीलता और महिला सशक्तिकरण

सड़क, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय, महाविद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, बैंक, बाजार और इंटरनेट जैसी सुविधाएँ महिलाओं के लिए अवसरों की वास्तविक भौगोलिक पहुँच निर्धारित करती हैं। उदाहरणतः बेहतर सड़क से विद्यालय और कार्यस्थल तक पहुँच आसान होती है; डिजिटल संपर्क से शिक्षा, बैंकिंग और बाजार सूचना तक पहुँच बढ़ती है। इसलिए अवसंरचना को महिला सशक्तिकरण के मध्यस्थ चर के रूप में देखना उचित है।

17. महिला सशक्तिकरण और क्षेत्रीय विकास का पारस्परिक मॉडल

जयपुर के संदर्भ में महिला सशक्तिकरण और क्षेत्रीय विकास का संबंध एक द्विदिशात्मक विकास चक्र के रूप में समझा जा सकता

है। शिक्षा और कौशल में वृद्धि रोजगार तथा उद्यमिता को बढ़ाती है; आय और वित्तीय स्वतंत्रता परिवार में निर्णय क्षमता को मजबूत करती है; निर्णय क्षमता से सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी बढ़ती है; यह भागीदारी स्थानीय संसाधनों और विकास प्राथमिकताओं के अधिक प्रभावी उपयोग में योगदान करती है; परिणामस्वरूप मानव विकास और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। विकसित क्षेत्र पुनः शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसंरचना और रोजगार के अधिक अवसर पैदा करके महिलाओं के अगले स्तर के सशक्तिकरण को संभव बनाता है।

इसे निम्न क्रम में प्रदर्शित किया जा सकता है : शिक्षा → कौशल → रोजगार/उद्यमिता → आय → निर्णय क्षमता → सामाजिक/राजनीतिक भागीदारी → स्थानीय विकास → बेहतर अवसर → आगे का महिला सशक्तिकरण।

18. स्थानिकता और क्षेत्रीय विषमता

भौगोलिक दृष्टिकोण का केंद्रीय प्रश्न यह है कि महिला सशक्तिकरण कहाँ अधिक है, कहाँ कम है और किन स्थानिक परिस्थितियों के कारण यह अंतर उत्पन्न होता है। जयपुर जिले के लिए तहसील, विकासखंड अथवा ग्राम-समूह स्तर पर महिला साक्षरता, रोजगार, स्वयं सहायता समूह, बैंकिंग, स्वास्थ्य सुविधाओं और बाजार पहुँच का मानचित्रण किया जा सकता है।

अनुसंधान की दृष्टि से चार आदर्श क्षेत्रीय प्रतिरूप प्रस्तावित किए जा सकते हैं— उच्च सशक्तिकरण-उच्च विकास, उच्च सशक्तिकरण-निम्न विकास, निम्न सशक्तिकरण-उच्च विकास तथा निम्न सशक्तिकरण-निम्न विकास। यह वर्गीकरण नीति-निर्माण के लिए स्थान-विशिष्ट हस्तक्षेप तय करने में सहायक हो सकता है।

19. महिला सशक्तिकरण सूचकांक : प्रस्तावित रूपरेखा

पीएच.डी. स्तर के अनुभवजन्य अध्ययन के लिए महिला सशक्तिकरण सूचकांक का निर्माण उपयोगी होगा। सूचकांक में शिक्षा, आर्थिक भागीदारी, सामाजिक निर्णय क्षमता, राजनीतिक सहभागिता, संस्थागत जुड़ाव और डिजिटल पहुँच को सम्मिलित किया जा सकता है। प्रत्येक संकेतक को मानकीकृत कर संयुक्त सूचकांक बनाया जा सकता है।

प्रमुख संकेतक	आयाम
महिला साक्षरता, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा	शिक्षा
रोजगार, स्व-रोजगार, आय, बैंकिंग	आर्थिक
स्वास्थ्य, गतिशीलता, निर्णय क्षमता	सामाजिक
पंचायत/नगर निकाय सहभागिता	राजनीतिक
स्वयं सहायता समूह, ऋण, सरकारी योजनाएँ	संस्थागत
मोबाइल, इंटरनेट, डिजिटल बैंकिंग	डिजिटल

20. क्षेत्रीय विकास सूचकांक और सांख्यिकीय विश्लेषण

क्षेत्रीय विकास सूचकांक में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बैंकिंग, रोजगार, बाजार, डिजिटल संपर्क और आय जैसे संकेतकों को शामिल किया जा सकता है। महिला सशक्तिकरण सूचकांक और क्षेत्रीय विकास सूचकांक के बीच पियर्सन सहसंबंध गुणांक द्वारा संबंध की दिशा एवं तीव्रता मापी जा सकती है। प्रतिगमन विश्लेषण से यह जाँचा जा सकता है कि शिक्षा, रोजगार, वित्तीय समावेशन और राजनीतिक सहभागिता में कौन-सा घटक क्षेत्रीय विकास पर अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव डालता है। ग्रामीण तथा नगरीय समूहों की तुलना के लिए टी-परीक्षण तथा अनेक समूहों के लिए विचरण विश्लेषण उपयोगी होगा।

21. राजस्थान की नीतियाँ और महिला सशक्तिकरण

राजस्थान में महिला सशक्तिकरण के लिए आजीविका, स्वयं सहायता समूह, उद्यमिता, वित्तीय समावेशन, शिक्षा, स्थानीय शासन और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विभिन्न संस्थागत कार्यक्रम संचालित हैं। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 में महिला उद्यमों तथा स्वयं सहायता समूह उत्पादों के विपणन से संबंधित प्रगति का उल्लेख मिलता है। ऐसे कार्यक्रमों का जिला स्तर पर मूल्यांकन केवल लाभार्थियों की संख्या से नहीं, बल्कि आय, रोजगार, बाजार पहुँच, निर्णय क्षमता और जीवन-स्तर में परिवर्तन के आधार पर किया जाना चाहिए।

22. जयपुर में महिला सशक्तिकरण की प्रमुख चुनौतियाँ

ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और रोजगार अवसरों का अंतर।

महिला-पुरुष शिक्षा तथा कौशल का अंतर।

महिलाओं के अवैतनिक घरेलू और पारिवारिक श्रम का आर्थिक मूल्यांकन न होना।

गतिशीलता, सुरक्षा और सामाजिक मानदंडों के कारण रोजगार तथा उच्च शिक्षा तक सीमित पहुँच।

बैंक खाता होने और वास्तविक वित्तीय स्वायत्तता के बीच अंतर।

डिजिटल उपकरणों की उपलब्धता तथा डिजिटल कौशल के बीच अंतर।

परिवार, विवाह और देखभाल संबंधी दायित्वों का महिला के आर्थिक समय पर प्रभाव।

सूक्ष्म उद्यमों के लिए पूँजी, विपणन और तकनीकी सहायता की सीमित उपलब्धता।

23. प्रमुख विश्लेषणात्मक निष्कर्ष

पहला, जयपुर की अपेक्षाकृत उच्च साक्षरता और नगरीकरण महिला सशक्तिकरण के लिए अनुकूल आधार उपलब्ध कराते हैं, लेकिन महिला-पुरुष शिक्षा अंतर अभी भी विकास की लैंगिक विषमता को दर्शाता है।

दूसरा, नगरीय अर्थव्यवस्था महिलाओं को सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और डिजिटल क्षेत्र में अवसर प्रदान करती है, जबकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, सूक्ष्म उद्यम तथा स्वयं सहायता समूह अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

तीसरा, स्वयं सहायता समूह महिला आर्थिक सशक्तिकरण, वित्तीय समावेशन और सामुदायिक नेतृत्व के बीच सेतु का कार्य करते हैं।

चौथा, महिला उद्यमिता स्थानीय आय, बाजार और रोजगार सृजन से जुड़ी है, इसलिए इसका प्रभाव परिवार से बाहर क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था तक जाता है।

पाँचवाँ, महिला सशक्तिकरण और क्षेत्रीय विकास का संबंध सरल कारण-परिणाम के बजाय पारस्परिक और चक्रीय प्रक्रिया के रूप में समझना अधिक उपयुक्त है।

छठा, जयपुर जिले में स्थानिक विश्लेषण इसलिए आवश्यक है क्योंकि राजधानी के नगरीय प्रभाव और ग्रामीण संसाधन क्षेत्रों के बीच अवसर संरचनाओं में भिन्नता मौजूद है।

24. नीति संबंधी सुझाव

तहसील और विकासखंड स्तर पर महिला सशक्तिकरण की स्थानिक प्रोफाइल तैयार की जाए।

ग्रामीण क्षेत्रों में माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के साथ सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था मजबूत की जाए।

महिला उद्यमिता के लिए ऋण, कौशल, बाजार, डिजिटल विपणन और मार्गदर्शन को एकीकृत पैकेज के रूप में उपलब्ध कराया जाए।

स्वयं सहायता समूहों को केवल बचत-ऋण इकाई न मानकर उत्पादन, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और विपणन से जोड़ा जाए।

महिला जनप्रतिनिधियों के लिए वित्तीय प्रबंधन, स्थानीय योजना और नेतृत्व प्रशिक्षण संस्थागत रूप से नियमित किया जाए।

स्वास्थ्य एवं डिजिटल सुविधाओं के स्थानिक अंतर को कम करने के लिए पिछड़े क्षेत्रों में प्राथमिकता आधारित निवेश किया जाए।

महिला श्रम की दृश्यता बढ़ाने के लिए स्थानीय स्तर पर भुगतानयुक्त और अवैतनिक कार्य से संबंधित सर्वेक्षण किए जाएँ।

25. निष्कर्ष

जयपुर जिले में महिला सशक्तिकरण और क्षेत्रीय विकास का संबंध बहुआयामी, पारस्परिक और स्थानिक प्रकृति का है। महिला शिक्षा, आर्थिक भागीदारी, वित्तीय स्वतंत्रता, सामाजिक निर्णय क्षमता, राजनीतिक सहभागिता और संस्थागत नेटवर्क क्षेत्रीय विकास की उत्पादक शक्तियों को मजबूत करते हैं। दूसरी ओर बेहतर सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बाजार, बैंकिंग और डिजिटल संपर्क महिलाओं को आगे के अवसर प्रदान करके उनके सशक्तिकरण को बढ़ाते हैं।

जयपुर की स्थिति यह संकेत देती है कि अपेक्षाकृत विकसित नगरीय संरचना अपने आप महिला समानता सुनिश्चित नहीं करती। विकास के लाभों का वास्तविक प्रभाव अभी माना जाएगा जब महिलाएँ संसाधनों तक पहुँच, उपयोग और नियंत्रण—तीनों स्तरों पर सक्षम हों। इसी प्रकार ग्रामीण महिलाओं को केवल कल्याण योजनाओं की प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था की उत्पादक और निर्णायक इकाई के रूप में देखना आवश्यक है।

अतः जयपुर जिले के लिए क्षेत्रीय विकास की ऐसी रणनीति अधिक उपयुक्त होगी जो महिला सशक्तिकरण को विकास की परिधि पर नहीं बल्कि केंद्र में रखे। शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य, सुरक्षित गतिशीलता, वित्तीय समावेशन, डिजिटल साक्षरता, उद्यमिता और राजनीतिक क्षमता का समन्वित विस्तार महिलाओं की क्षमताओं को मजबूत कर सकता है। अंतिम रूप से यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया जा सकता है कि महिला सशक्तिकरण विकास का मात्र परिणाम नहीं, बल्कि विकास की सक्रिय उत्पादक शक्ति है।

संदर्भ सूची

1. भारत सरकार। (2011)। भारत की जनगणना 2011 : जिला जनगणना पुस्तिका, जयपुर। भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय।
https://censusindia.gov.in/nada/index.php/catalog/1069/download/3290/DH_2011_0812_PART_B_DCHB_JAIPUR.pdf
2. भारत सरकार। (2011)। जयपुर जिला: प्राथमिक जनगणना सारणी। भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय। <https://www.censusindia.gov.in/nada/index.php/catalog/6301/study-description>
3. राजस्थान सरकार। (2025)। आर्थिक समीक्षा 2024-25। वित्त विभाग, राजस्थान सरकार। <https://finance.rajasthan.gov.in/docs/budget/statebudget/2025-2026/EconomicReviewE.pdf>
4. राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। जिला-वार राजीविका स्वयं सहायता समूह प्रतिवेदन। <https://rgavp.rajasthan.gov.in/Content/DownloadManager/0039e285-5f8f-4af3-b0ed-d54f695261fd.pdf>
5. राजस्थान सरकार, शिक्षा विभाग। जनगणना 2011 के आधार पर राजस्थान के जिलों की लिंगानुसार साक्षरता दर। <https://education.rajasthan.gov.in/pages/department-page/206>
6. केंद्रीय भूजल बोर्ड। जयपुर जिला: भूजल सूचना रिपोर्ट। भारत सरकार। <https://cgwb.gov.in/sites/default/files/2022-10/jaipur.pdf>
7. सेन, अमर्त्या। (1999)। विकास एक स्वतंत्रता के रूप में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
8. नुसबाम, मार्था। (2000)। महिला और मानव विकास: क्षमता दृष्टिकोण। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।
9. कबीर, नायला। (1999)। पसंद करने की शक्ति: बांग्लादेशी महिलाओं और श्रम के संदर्भ में अध्ययन। वसों।
10. विश्व बैंक। (2012)। विश्व विकास रिपोर्ट : लैंगिक समानता और विकास। विश्व बैंक।
11. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। (2020)। मानव विकास रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम।
12. संयुक्त राष्ट्र महिला। (2023)। महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता संबंधी वैश्विक प्रतिवेदन। संयुक्त राष्ट्र।
13. भारत सरकार। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय।
14. भारत सरकार। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय: वार्षिक प्रतिवेदन।